THE FOOD CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2001.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : उपसभापति महोदया, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :-

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदया, इस बिल का उद्देश्य केवल जो क्रेडिट लिमिट फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की है उसको बढ़ाना है। सैक्शन 27 फूड कारपोरेशन एक्ट के मुताबिक पेड अप कैपिटल से दस गुना अधिक तक हमारी क्रेडिट लिमिट हो सकती थी और पेड अप कैपिटल 2294.50 था तो उसके मुताबिक प्रोक्योरमेंट करने के लिए हमारी अधिकतम लिमिट 22945 थी, लेकिन पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन से पहले यह अनुमान लगा कि अब प्रोक्योरमेंट अधिक करनी होगी और अधिक प्रोक्योरमेंट करनी होगी तो अधिक धन की हमें आवश्यकता होगी और यह अनुमान लगा कि हमारी आवश्यकता लगभग 26, 27 हजार करोड़ रुपया हो सकती है। जब यह बात आई तो उस समय संसद का सत्र नहीं था, आर्डिनेंस करना पड़ा, आर्डिनेंस किया और अब उसको बढ़ाने के लिए हम यहां पर आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्डिनेंस की आवश्यकता पड़ी और आर्डिनेंस करने का हमको लाभ हुआ। क्योंकि मई में हमारा स्टॉक 30 हजार था और हमने 23 हजार करोड़ रुपये अवेल किये, जून में 31 हजार हमारा स्टॉक था और हमने 26 हजार करोड़ रुपये अवेल किये, जुलाई में हमे 27 हजार करोड़ रुपया अवेल करना पड़ा प्रोक्योरमेंट में, अर्थात आर्डिनेंस न किया होता तो प्रोक्योरमेंट का जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वह बीच में रुक जाता इसलिए उस समय आर्डिनेंस करना पड़ा। अब वह जो रोक है, जो लिमिट हमारी है फूड कारपोरेशन की उसको बढ़ाने के लिए सैक्शन 27 में अमेंडमेंट लेकर के हम इस सदन में आये हैं।

The question was proposed.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Respected Madam, first of all, I want to thank you for the opportunity that you have given me to speak on this Bill. The proposed amendment is to increase the borrowing capacity of the Food Corporation of India and this deserves the support of the House. But, keeping this in view, I would like to say, at present, all the godowns are filled with grains and the Government is not in a position to buy more foodgrains from the farmers. Because of this, the condition of the farmers became very critical. The result is: The farmers started committing suicides. This is due to fall in the prices of foodgrains. This is the condition of our farmers. Now, the Government is taking full care about it and we all know about it. Our first and the foremost duty is to protect our farmers. Being a Member of the Standing Committee on Food and Civil Supplies, I had an opportunity to visit some of the godowns. We had seen the condition of the godowns. The godowns are full of grains. There is no place to store foodgrains properly. We all know about the climatic

conditions. There were heavy rains and there were sudden climatic changes in our country. The foodgrains are also stocked in a verandah. The foodgrains are being dumped in bags. There is no proper storage facility. The condition of godowns is such that even the medicines which are used to prevent the foodgrains from getting deteriorated, cannot be put. When we went for inspection, we were told that, every month, they put medicines and all that. But the godowns are full to such an extent that whosoever wants to put the medicines, can only put them around the bags. The situation is such that nobody can do anything. They cannot even lift the bags; they can't even put the medicines. As they cannot put the medicines, a large quantity of foodgrains is deteriorating. All this is happening because of the lack of storage facilities. Whenever we go there, they make a complaint that godowns are not available; and, the godowns which are available are completely full. They even tried to take some godowns on hire basis, but that was not possible. Therefore, I would like to say that whatever foodgrains are available, the Government should take proper care of that. It can send those foodgrains to the States where people are dying of hunger. When we ask the States, they say 'we are not getting the foodgrains'; and, when we ask the Central Government, it says, 'the State Governments are not lifting the foodgrains.' This way, one Government is putting the blame on the other Government. As a result, the foodgrains are deteriorating. During the discussion, they even expressed the view that they wanted to export the foodgrains because they were not getting proper rates here. The Government should not think about the rates; it should not think about exporting the foodgrains. In some States, the people are dying of hunger. For example, in Orissa, 25 people died because there was no food. So, the Government should send these foodgrains to such areas either at a low price or free so that the lives of the people, who are dying of hunger, could be saved.

Madam, the first thing the Government should do is, to try to vacate the godowns which are full of grains and then purchase foodgrains to be put into them. The main thing is, they must try to distribute the foodgrains amongst the States. The Government should put pressure on the States to lift the foodgrains. Another thing I would like to mention is about the rates. What is happening is this. The rate of rice in the PDS shops and the rate of rice in the markets is almost equal. There might be a difference of one rupee or so. If a person gets good quality rice from the market at the rate of Rs.11 or Rs.12 per kg, why would he go to the PDS shop to purchase the rotten rice, the price of which is about Rs.10/- per

kg? This is the psychology of the people; you should understand it. This is why, the PDS shops are running short of customers and the foodgrains are not being lifted by the States. So, the Government should lower the rate of rice in PDS shops so that the poor people of this country could atleast have sufficient food. The way these foodgrains are being destroyed, is not good for our country. On the one hand, you say the foodgrains are deteriorating; on the other, the people are dying of hunger. So, this kind of a situation is prevailing in our country. Madam, under the circumstances explained, I think, merely enhancing the purchase power of the FCI is not the only immediate solution; it also needs a broader thinking, a wider vision, proper amendments and decisions, so as to ensure proper distribution of foodgrains and food to the needy in India.

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तरांचल) : उपसभापति महोदया, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के सैक्शन 27 में लाए जा रहे संशोधन के प्रस्ताव में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, प्रोक्योरमैंट किसान और अभावग्रस्त लोग, दोनों के फायदे का विषय है। देश में जब बड़ी मात्रा में अन्न पैदा होता है और मार्किट का जो स्वभाव है - जैसा कि सवेरे राजस्थान के बारे में चर्चा हो रही थी कि वहां बड़ी मात्रा में ज्वार और दूसरी फसलें इस साल पैदा होने वाली हैं और दो सौ रुपये के आसपास के ठेके अभी से लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं तो यह एक प्रकार का हमारे समाज का स्वभाव बना हुआ है कि जब किसान फसल पैदा करता है तो उसकी वस्तुओं को बहुत कम दाम में क्रय किया जाता है लेकिन जब वही लोग विक्रय करते हैं तो वह काफी बड़ी मात्रा में होता है। इसी कारण से किसान निरंतर गरीब होता चला जाता है। यह जो सरकारी खरीद होती है, सरकार का समर्थन मूल्य होता है उससे किसान को भी शक्ति प्राप्त होती है, किसान को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। समाज में या देश के विभिन्न भागों में जहां अन्न कम पैदा होता है या जहां कम क्रय शक्ति के लोग हैं उन्हें सरकार एक नियत दाम पर यह खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इस कारण से सरकार पर यह दायित्व निरंतर पड़ता है। बढ़ती हुई आबादी के कारण सरकार को क्रय करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता निरंतर पड़ती है। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि सरकार के पास जो धन है, सरकार के द्वारा जो राजस्व वसूली की जाती है, जो जनता का धन है उसका बड़े स्तर पर कोई बहुत अच्छा सदुपयोग नहीं होता है। इसका मुख्य कारण हमारे प्रशासनिक तंत्र में आए दोष हैं। हमारे प्रशासन तंत्र में अनेक प्रकार के आर्थिक लाभ के लिए गठजोड़ होते हैं और उसका जो प्रभाव पड़ता है उससे अनेक बार सरकारों को - सरकार चाहे जो भी रही हो एक प्रकार की बदनामी उठानी पड़ती है और इसके कारण खाद्य विभाग से संबंधित जो अनेक यूनिटें हैं उन्हें लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और उन्हें अपयश प्राप्त होता है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं उन्होंने इस सदन में और दूसरे सदन में भी इन दोषों के बारे में स्वीकृति जाहिर करते हुए इन्हें सुधारने का संकल्प व्यक्त किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो अन्न भंडारों में लाया जाता है उसका क्षय कम से कम हो, उसकी चोरी कम से कम हो और आज जो उसके सड़ने की स्थिति आई है -अभी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के मामले में एक निर्देश दिया है कि जहां अन्न भंडारों में भरा हुआ है और लोग भूखे हैं वहां की सरकार का यह दायित्व है कि उन्हें अन्न उपलब्ध कराए। जहां तक निर्यात की बात है तो सरकार ने 4100 रुपये मीट्रिक टन के भाव पर निर्यात करने की घोषणा की

है। सरकार देश में बढ़े हुए दामों को कम करे, सरकार ने कम किए भी हैं लेकिन थोड़े समय के लिए कम किए हैं। मार्च, 2002 तक के लिए सरकार ने 25 प्रतिशत दामों में कमी की है। आज अन्न सड़ रहा है और लोगों को आवश्यकता भी है पर देश में क्रय शक्ति नहीं है, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है तो सरकार को दाम और कम कर देने चाहिए। सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उसने अत्यंत गरीब लोगों, वृद्ध लोगों, जो क्रय नहीं कर सकते, जो बेसहारा हैं, के लिए **अन्त्योदय अन्न योजना** चलाई है। लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो योजना सरकार चलाती है, उसका लाभ उन लोगों को प्राप्त हो रहा है या नहीं, जिनके लिए योजना बनाई गई है। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि सरकार की जो मशीनरी है, जिले में डीएम है,जिला अधिकारी है, डीएसओ है, जिला पूर्ति अधिकारी हैं, उनके साथ साथ इसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। इस के लिए वहां के जो विधायक हैं, उनको भी इससे जोड़ना चाहिए और अगर किसी भी इलाके में लोग भूख से मरते हैं तो इसका दायित्व उन पर आना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी उन पर आनी थाहिए। देश में अन्न का इतना विशाल भंडार है और यहां लोग भूख से मरें यह पूरे देश के लिए, देश की सौ करोड़ जनता के लिए एक अपमान का विषय है, पूरे देश के लिए पीड़ा का विषय है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है, चाहे वह हिन्दू हो या किसी भी मत के मानने वाले हों, उन सब में नैतिक मूल्यों का आग्रह है। लेकिन जो औद्योगिक प्रभाव, औद्योगिक सुधार का असर समाज पर पड़ा है, उसने हमारे नैतिक मूल्यों को क्षरित किया है, कमजोर किया और इसके कारण कैसे भी अधिक पैदा करने की वृत्ति, कैसे भी अधिक धन पैदा करने की वृत्ति और कैसे भी अधिक भोगने की वृत्ति पूरे समाज में घर कर गई है। यह किसी व्यक्ति, किसी वर्ग, किसी जाति या किसी धर्म का विषय नहीं है। सम्पूर्ण वर्गों में यह प्रवृत्ति आई है, सम्पूर्ण समाज में आई है। इसके कारण समाज में अनेक प्रकार के दोष पैदा हुए हैं।

महोदया, आज लाखों लाख टन अनाज चूहे खा जाते हैं। वे मूर्त चूहे हों या अप्राकृतिक चूहें हो, यह दूसरी बात है, लेकिन चूहे अनाज खा जाते हैं। मेरा आग्रह है ये चीजें धीरे-धीरे कम होनी चाहिए। जब मैं कम होने की बात कहता हूं तो मेरे कहने का अर्थ है कि इसको ठीक करने के लिए आपको गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जीवन राजनैतिक दृष्टि से बड़ा पवित्र और अच्छा रहा है। मैं आपके नजदीकी प्रांत का हूं और आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं और चाहता हूं कि आप अपने इस कार्यकाल में इस दिशा में सफल हों। आप अगले साल के लिए यह सुनिश्चित कर दें कि हमारा अन्न का एक दाना सड़ेगा नहीं, हमारा अन्न का एक दाना जाया नहीं जाएगा। सुनने में आता है कि अन्न की बोगी मद्रास गई तो वह वहां पहुंची नहीं। मद्रास से कलकत्ता के लिए बोगी चली लेकिन वह नहीं पहुंची। इस तरह की बातें इस देश में घट रही हैं। इसलिए इसके लिए किसी न किसी पर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। हमारे यहां लेबर यूनियन और दूसरे कर्मचारियों के संगठनों की बात होती है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के दायित्व के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा और इस दायित्व के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार बनाना होगा। जिन लोगों को काम सौंपा गया है, जिन लोगों को दायित्व ओढ़ाया गया है अगर वह काम पूरा नहीं होता तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको साधारण दंड नहीं, बल्कि उनकी नौकरी जानी चाहिए क्योंकि इस देश में लोगों को नौकरी भगवान से बड़ी लग रही है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की नौकरी पर ही चोट करनी चाहिए और जो अपने कर्तव्य में विफल होता है, जो अपने दायित्व में विफल होता है उसकी नौकरी जानी चाहिए। यह जो फूड कारपोरेशन है उसमें जो कर्मचारी

भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जाते हैं, उनकी तुरन्त नौकरी जानी चाहिए और ऐसा नियमों में प्रावधान करना चाहिए। लाखों टनों अन्न जो इस तरह से जाया होता है और चूहे खा जाते हैं, तो चूहे खाते होंगे, चूहे तो जमीन में भी खाते हैं लेकिन उसमें किसान की घटती नहीं होती है। यह तो ऐसी हुआ जैसे कि :

तुलसी पक्षिन के लिए सरिता घटे न नीर,
धर्म से धन ना घटे जो सहाय रघुवीर।

यह तो वैसे ही है। किसान के चूहे के खाने से घटता नहीं। लेकिन यहां जो काल्पनिक चूहे ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, उनके कारण यह घटौती आती है और उससे देश को नुकसान होता है।

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस दिशा में कठोर प्रयास करें ताकि भविष्य में कोई इस तरह की छिज्जत न हो, लाखों टन का नुकसान न हो और अन्न सड़े नहीं। महोदय, मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं। वहां के गोदामों में पिछले वर्ष बहुत अन्न सड़ गया और वह इसलिए सड़ गया क्योंकि भंडारण ज्यादा हो गया। लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं थी। वे उसे 10 रुपए किलो में नहीं खरीद सकते थे। साथ ही ओपन मार्केट में दाम कम हो गए। इससे कंट्रोल के गेहूं के दाम ज्यादा हो गए। परिणाम यह हुआ कि सारा का सारा अन्न सड़ गया। अब सरकार उसको फेंकेगी या बेचेगी यह हमें नहीं मालूम। लेकिन यह फेंकने और बेचने की स्थिति भविष्य में नहीं आनी चाहिए। एक निश्चित प्रक्रिया बनाइये, इधर से आएगा डम्प होगा साल का, जो साल का डम्प होगा यह बाहर निकलेगा। अगर ऐसी कोई सुनिश्चित व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था का जो पालन नहीं करेंगे, उनको दण्डित किया जाएगा, जहां जहां भी अन्न सड़ेगा, उसके लिए वे अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे तो शायद हम देश के जो अभावग्रस्त लोग हैं, बचे हुए अन्न को उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जिस तरह से आप निर्यात के लिए अन्न सस्ता कर रहे हैं, उसी तरह से जो आवश्यकता वाले लोग हैं 40 परसेंट या उसके ऊपर, 40 परसेंट के ऊपर वाले लोग भी हैं जो सरकारी अन्न पर निर्भर करते हैं। गांवों में ऐसे लोग हैं जिनके खेत नहीं हैं। हमारे पहाड़ों में तो सारे ही लोग हैं, सब कंट्रोल का ही खाते हैं, जो अपने को बड़ा कहते हैं, वह लोग भी कंट्रोल पर लेने के लिए लाइन में जाते हैं। बंगाल में भी ऐसी स्थिति है। हम उन सब को भी कम मूल्यों पर दें। सरकार अपनी व्यवस्था को सुधारे, अधिक दाम न ले बल्कि अपनी व्यवस्था को सुधारे। अव्यवस्था के कारण जो घाटे हैं, उनको कम करे और समाज को लाभ पहुंचाए। यह जो सरकार का अधिक पैसा खरीद करने के लिए है, यह समय की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत।

SHRI C.O. POULOSE (Kerala): Madam Deputy Chairman, the Food Corporations (Amendment) Bill, 2001 is a very simple Bill. But the amendment is important, in the present day context. The aim of the Bill is to remove the limitation of borrowing by the FCI. This is required by the FCI for procurement and for stock holding. The stock is increasing day by day. The offtake is very low. It has been reported that around 60 million tonnes of foodgrains is with the Food Corporation of India. It costs round about Rs.58,000 crores. The arbitrary decision of the Government to distinguish

between the BPL and the APL has kept around 75 per cent of the population out of the purview of the Public Distribution System. They have to purchase foodgrains from the PDS 'at the economic price'. According to the FCI, the economic cost is calculated taking into account different factors. The economic cost, in almost all the cases, is above the prevailing market price. Nobody is willing to purchase at a higher price from the PDS. The economic cost is calculated by adding all other costs, incurred by the FCI like the cost of procurement, the cost of transport, the loss incurred during transportation and storage, interest cost and godown cost. This is how every is added. When everything is added, naturally, the economic price is always above the market price. Then, nobody is prepared to buy rice or wheat from the PDS. Hence the offtake from the FCI is diminishing day by day.

Most of the APL families are poor people. If we have a cursory look at the BPL definition, around Rs.49.06 for the rural population and around Rs. 56 for the urban population, as the boundary level for the BPL, is calculated, based on 1973-74 price level.

That definition itself shows that those who are above the poverty line are not well-to-do people. They cannot purchase rice or wheat from the public distribution system at an increased price. So, they are compelled to purchase wheat and the other foodgrains needed, from the open market. There is a variety of foodgrains to be purchased. That is the position. Now, the Government is trying hard to get away the stocks from the godowns. The Government has increased the quota of foodgrains for the BPL it was ten kilograms and now it is 20 kilograms; the Government is distributing foodgrains free of cost to the drought-prone areas; there is open market sale at reduced prices; the Government is selling, trying to sell, foodgrains in the open market in other ways; there are also attempts to export foodgrains at lower prices. By all these methods, the Government is trying its level best to reduce the stock. But the stock is not reducing. The stock is increasing day by day. What is the problem? The point is that the procure foodgrains from the peasants of this country should be properly, evenly and uniformly distributed throughout the length and breadth of the country. But the Government, in the name of giving up subsidies, has made a diversion and that has created a dilemma for the Food Corporation of India. That is the problem the FCI is now facing. Not only that. According to the replies in this House and in the other House, the Government is trying to grant loans to the SAARC countries to get away the wheat we are holding today.

There are proposals for barter trade of wheat. That also is aimed at reducing the stock. Export is being promoted to get away the stock. The Food Corporation of India is now facing this dilemma because of the new public distribution system and the policy adopted by the Government two years back. If this policy is continued, the procurement of foodgrains from the peasants will be the main casualty. The purpose for which the FCI was incorporated was to procure paddy, rice, wheat as well as other coarse grains. Now the FCI is incapacitated because of this growing foodgrains stock. So, I request the Government to review this exercise, the new policy of public distribution system, to have a thorough review. I request the Government to have a universal and widespread distribution system, giving relief to the common people of this country. That is what is necessary.

Madam, I want to point out certain immediate demands of the FCI workers. There are about 70,000 workers in the FCI. A long-term settlement relating to their wages was made upto 1997. Now, I understand that there was an understanding between the unions and the management about the wage revision and the proposal is lying with the Ministry of Finance. I request the Government to immediately approve this understanding and implement the wage revision.

The second point is, recognition of trade unions. It is in the mid-stream. There are several unions, and the unions should be recognised through a secret ballot. The process is now in mid-stream. I request the Government, especially the Central Labour Commissioner who is conducting the exercise, to have discussions with all the unions and iron out the differences between the management and the unions and to see that the recognition of trade unions is done at the earliest.

The third point is this. The main workforce in the Food Corporation of India are the head-load workers who are handling huge stocks of foodgrains. There are about two-and-a-half lakh workers. Many of them have been brought under the direct payment system. But even now, there are many workers who are out of this system. I request the Government to bring all these head-load workers or handling workers into the fold of the direct payment system and to implement proper service conditions for them. In several of the godowns, there is no drinking water facility; there are no urinal facilities for lady workers; like that, there are so many problems.

I request the Government, especially, the Minister, to see that proper working conditions are created for the workers, the headload workers in particular. Lastly, I want to stress one point that there are heavy losses, because of lack of storage capacity, and so many other problems are there in the management. The management at the higher level is trying to victimise the workers, especially, the workers connected with the unions, to a great extent. There are unwanted transfers also. I request the Government, especially, the Minister, to look into these aspects and see that the FCI is run properly by giving fair treatment to the workers. That is what I want to say. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. P.G. Narayanan has to go to a meeting. There are two speakers before him, that is, Sardar Balwinder Singh Bhundar and Shri S. Viduthalai Virumbi. But before I call you, the Finance Minister would lay the Budget (Manipur) 2001-2002 on the Table of the House.

THE BUDGET (MANIPUR) 2001-2002

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of Manipur for the year 2001-2002 (Annual Financial Statement). [Placed in Library. *See* No. L.T. 4011/01]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. P.G. Narayanan. Mr.Narayanan, you have three minutes, in any case.

THE FOOD CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL, 2001 - Contd.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Madam, the Amendment sought by the Government, is to provide an increased borrowing capacity to the F.C.I. There are many anomalies in the Food Corporation of India, which would not be removed by bringing this small amendment. The Government has brought this amendment to raise the loan from the nationalised banks and the Reserve Bank of India. The maximum credit could be ten times of the Reserve Fund, but the Reserve Fund position of the Food Corporation of India is very poor. So, this Bill will not meet the present needs of the Corporation. The foodgrains production has doubled because farmers have taken more interest in producing more. The FCI is having many problems